SHORT NOTICE QUESTION

बलिया-बेरिया बांध

+

*29. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री शिवचरण लाल :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलिया-बेरिया बांध को ग्राम गाय घाट पर गंगा नदी कई वर्षों से काट रही है और इस वर्ष बांध के पूरी तरह कट जाने की आशंका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री से हुई बातचीत के पश्चात् भी सरकार इस कार्य में देरी कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). पिछले कुछ वर्षों के दौरान गंगा अपने बायें किनारे पर गया घाट ग्राम के समीप कटाव करती रही है और बलिया-बेरिया बांध की सुरक्षा को खतरा पहुंचाती रही है । पिछले दो वर्षों के दौरान इस समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है । राज्य सरकार नदी के और अतिक्रमण को रोकने के लिये कुछ कार्य कर रही है । बांध की स्थायी सुरक्षा के लिए हाल ही में मॉडल अध्ययन किए गये हैं जिनसे ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र की कारगार सुरक्षा हेतु चार पक्की ठोकरों तथा पांच जलमग्न बारों (Bars) की व्यवस्था होनी चाहिये । इस कार्य पर 1·5 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । धन की कमी होने के कारण राज्य सरकार स्थायी कार्य आरंभ करने में कठिनाई महसूस कर रही है । बहरहाल, वे आगे कटाव को रोकने के लिए आवश्यक अस्थायी सुरक्षा कार्य करने का विचार रखते हैं । बूट की सुरक्षा के लिए अपेक्षित सामग्री के एकत्रण तथा परिवहन का काम किया जा रहा है ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन से इस वर्ष बांध बचेगा नहीं । टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन का कार्य करीब चार पांच सालों से चल रहा है जिस पर करीब पचास लाख रुपया खर्च हो चुका है । डा० के० एल० राव वहां गए थे । परमानेन्ट प्रोटेक्शन करने के लिए डेढ़ करोड़ का खर्चा आएगा जबकि टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन पर ही पचास लाख खर्च हो गया है । वहां की स्थिति की भयंकरता को देखते हुए वित्त मंत्री का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ है और उस कार्य पर सहायता करने के लिए जांच भी की जा रही है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को आर्थिक सहायता देने के लिए लिखित आश्वासन देगी ताकि जो प्रोटेक्शन का कार्य है वह वहां पर आरम्भ किया जा सके ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : The Government of India also attaches great importance to this work and we have been impressing on the U.P. Government that they should do this work. With regard to financial assistance, flood control is essentially done by the State, and U.P. Government must first spend the money allotted in the plan for this and other work. The question of financial assistance does not arise at this stage.

श्री चन्द्रिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि फ्लड कन्ट्रोल स्टेट सब्जेक्ट है । उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, आठ करोड़ रुपया पांच वर्ष के लिए कोई माने नहीं रखता है, आपने भी इतना रुपया दिया लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो क्या भारत सरकार हमको भगवान के सहारे छोड़ देगी ? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार काम न करे तो वहां से एक दो मील पर रेलवे लाइन है और अगर बांध कट जाता है तो वह सारी लाईन साफ हो जायेगी । दो तिहाई जिला बर्बाद हो जायेगा । चालीस पचास हजार की आबादी और हजारों मवेशी

बर्बाद हो जायेंगे और कई करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी । एसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं रेल मंत्रालय से कि लाइन को बचाने के लिए आई० डब्लू० टी० के माल होने वाले जहाज पर्याप्त मात्रा में बेकार पड़े हैं उन्हें डेहरी सोन तथा चुनार से मंगाकर ग्राम गाय घाट पर गंगा में पत्थर के टुकड़े डालने का कार्य युद्ध स्तर पर करेंगे ताकि बांध शक्तिशाली हो कर गंगा के कटाव का मुकाबला करने में समर्थ हो सके ?

DR. K. L. RAO : I have already submitted that this work is of very great importance and what the hon. Member has said is entirely correct. If there is a breach it will cause very severe loss to a large area of land and will put into trouble a lot of people, more than 15,000. The provision that has been made in the State Plan for this, namely, Rs. 1½ crores, must be spent before they approach for any assistance.

श्री शिव चरण लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, डा० के० एल० राव इस भयंकर स्थिति को ध्यान में रखकर दो बार बलिया गये हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि गंगा के कटाव से बचाने के लिए वहां की दुखी जनता को मंत्री महोदय ने आश्वासन दे रखा है ? यदि हां, तो इस योजना को केन्द्रीय योजना मान कर जल्दी से इस पर कार्य क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है ?

DR. K. L. RAO : I have inspected this bund twice. I have also come to the conclusion that at this stage we must fight out the river. Accordingly, the State Government should take up the necessary steps. I hope the State Government will take those necessary steps to ensure that there is no breach here.

श्री सत्य नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने मंजूर किया है कि परिस्थिति बड़ी गम्भीर है और वह और भी विकट होती जा रही है जिससे बहुत बड़े पैमाने पर जन, धन और पशु का विनाश होने वाला है तो उस क्षति से उस जिले को बचाने के लिए इस योजना को प्राथमिक स्थान देकर फौरन उस पर कार्य शुरू करने की व्यवस्था करेंगे ?

DR. K. L. RAO : That is what I have submitted. We are urging the State Government to give it high priority. We have requested the Chief Minister also to look into it.

SHRI BISHWANATH ROY : In view of the fact that at the time of preparation of the Five Year Plan no State Government or the Central Government can make any exact estimate regarding the loss that may be due to natural calamities like floods and erosion by the turbulent rivers. May I know whether the Government of India would take special steps for protection of the Bariya and Chittoni bunds as well as the property near those bunds so that in the future no assistance would be required either from this Government or the U.P. Government ?

DR. K. L. RAO : What the hon. Member said is quite true. We could not plan these things as we do in the case of projects like irrigation. That is correct. That is why we should make a lumpsum allotment for this in the State plan for new contingencies, new exigencies. With regard to the two bunds mentioned by the hon. Member, Chittoni bund and Balia-Bariya bund, these are bunds which have given a lot of trouble. I hope the U.P. Government would take the necessary steps in the case of Balia-Bariya bund.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, अभी अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि हमने राज्य सरकार को लिखा है और प्रधान मंत्री ने भी राज्य सरकार को लिखा है परन्तु वहां पर जो भयावह स्थिति है उसको देखते हुए यदि आपके और प्रधान मंत्री के आदेश को राज्य सरकार नहीं मानती है या उसमें विलम्ब करती है तो उस हालत में क्या आप उस कार्य को अपने हाथ में लेंगे ? अभी आपने बताया, प्रश्न के उत्तर में, कि डेढ़ करोड़ रुपया जब तक वे नहीं लगायेंगे तब तक हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं लेकिन अगर वे वह रुपया नहीं लगाते हैं तो उस दशा में इसकी गंभीरता को देखते हुए

क्या आप अपनी तरफ से तत्काल उस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हैं ?

DR. K. L. RAO : I appreciate the anxiety of the hon. Member. But it is not possible for the Centre to take it up. The State Government will have to take it up.

श्री मु० अ० खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जानते हुए जैसा कि मंत्री महोदय ने बतलाया है कि इस बांध की हालत बहुत ख़राब है और इस वर्ष बांध टूट सकता है, दो जिलों को इससे बहुत अधिक नुकसान पहुंचेगा तो जिस डेढ़ करोड़ रुपये का जिक्र मंत्री महोदय ने अपने जवाब में किया है कि वह किया जा चुका है तो क्या वह इस बांध के लिए दिया गया है लेकिन अगर वह दूसरे कार्यों के लिए दिया गया है तो जितने रुपये की कमी पड़ेगी उस को मंत्री महोदय फ्लड कंट्रोल के लिए दिये गये रुपये से पूरा करके जल्दी से जल्दी उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि उन दो जिलों में मरने वाले आदमियों और जानवरों की जानें बचाई जा सकें ?

DR. K. L. RAO : Sir, the provision made for this year for U.P. is Rs. 1·5 crores for the flood control work. Realising the importance of the flood control works in U.P. the Planning Commission is now engaged in an exercise whether this provision can be increased to Rs. 2 to 2·5 crores. Whatever it is, it is necessary that the State Government must go ahead with all out effort to complete these works and must spend the money, and if still money is required then the Central Government will naturally have to look into the problem.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Triangular Power Contest among U.S.A., U.S.S.R. and China in Indian Ocean in 70's

*1442. SHRI MUHAMMAD SHERIFF : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether he told in a meeting of the Parliamentary Consultative Committee of his Ministry that the Indian Ocean in the 70's would witness a triangular power contest among the United States, U.S.S.R. and China; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b). In accordance with the guidelines laid down in consultation with the Leaders of the Opposition Parties/Groups, to regulate the constitution and functioning of the Consultative Committees, no reference to the discussion held in the meetings thereof is to be made on the floor of the House.

Demand and Supply of Nylon Yarn

*1445. SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a report in the *Financial Express* of the 24th January 1970 stating that the Textile Commissioner has assessed the gap between demand and supply of nylon yarn at 11,000 tons; and

(b) if so, the steps, if any, taken to make up this gap ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) In view of the fact that the artsilk weaving industry is predominantly in the decentralised sector and the weaving units can and do easily switch over from one type of artsilk yarn to another, it is difficult to assess the demand for any one type of yarn accurately. Nevertheless, Government have issued licences/letters of intent for a total capacity of 18,600 tonnes of textile nylon yarn. The production of nylon yarn has been going up steadily and efforts are being made to ensure installation of the entire licensed capacity within a short time. Steps are also being taken to improve the availability of other types of artsilk fibres/yarns. To supplement the indigenous production, import of nylon yarn is also being arranged through the S.T.C. to the extent considered necessary to maintain prices at a reasonable level after taking into account the various relevant factors like consump-